



# राजपत्र, हिमाचल प्रदेश (असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, शनिवार, 23 मार्च, 2002/2 चैत्र, 1924

हिमाचल प्रदेश सरकार

राजस्व विभाग  
(स्टाम्प रजिस्ट्रेशन)

अधिसूचना

शिमला-2, 18 मार्च, 2002

संख्या 5-10/74-रैव० ए.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश में यथा लागू भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (1899 का II) की धारा-9 की उप-धारा (1) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों तथा हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार के पब्लिक सेक्टर उपक्रमों के कर्मचारियों एवं स्वायत्त निकायों के कर्मचारियों द्वारा हिमाचल प्रदेश सहकारी सोसाईटी अधिनियम, 1968 के अन्तर्गत रजिस्ट्रीकृत सभी सहकारी बैंकों तथा राष्ट्रीयकृत बैंकों से अपने निवास-गृह के निर्माण या क्रय के लिए अनुदत्त गृह निर्माण अग्रिम को सुनिश्चित करने के लिए ऐसे बैंकों के पक्ष में निष्पादित आडमान पत्तों अर्थात् बिला-कन्जा बन्धक पर प्रभार्य, पूर्ण स्टाम्प शुल्क की, समस्त हिमाचल प्रदेश में, तुरन्त प्रभाव से छूट देते हैं।

परन्तु यह कि स्टाम्प शुल्क में दी गई ऐसी छूट, प्रत्येक कर्मचारी को उसकी अपनी जीविका में केवल एक गृह निर्माण अग्रिम के लिए, दस लाख रुपये की अधिकतम सीमा के अध्येधीन होगी।

आदेश द्वारा,

रवि ढीगरा,  
वित्तायुक्त एवं सचिव।

[Authoritative English text of the Notification No. 5-10/74-Rev. A. dated 18-3-2002 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].

**REVENUE DEPARTMENT**  
(Stamp-Registration)

**NOTIFICATION**

*Shimla-171002, the 18th March, 2002*

**No. 5-10/74-Rev. A.**—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1) of section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (Act No. II of 1899) as applicable to the State of Himachal Pradesh the Governor, Himachal Pradesh, is pleased to remit the entire stamp duty chargeable on instruments of Hypothecation *i.e.* mortgage without possession executed by the employees of the Himachal Pradesh State Government and the employees of the Himachal Pradesh State Government Public Sector Undertakings and the employees of autonomous bodies for securing a house building loan from the Co-operative Banks registered under the H. P. Co-Operative Societies Act, 1968 and Nationalized Banks, for construction or purchase of a dwelling house for their own use and executed in favour of aforesaid banks, with immediate effect in the whole of Himachal Pradesh:

Provided that the stamp duty so exempted shall be for one H.B.A. per employee in his career further subject to the maximum ceiling of Rs. 10.00 lakhs.

By order,

**RAVI DHINGRA,**  
*Financial Commissioner-cum-Secretary.*

